JUST फेलोशिप

(JUST: Just and Sustainable Transitions)
समुदायों, परिदृश्यों और लोगों के वास्तविक जीवन अनुभवों से उभरते परिवर्तन के रास्तों का दस्तावेज़ीकरण

समता और सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की एक पहल

पृष्ठभूमि और तर्क

न्यायपूर्ण परिवर्तन (Just Transition) का अर्थ है अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को अधिक टिकाऊ और पारिस्थितिक रूप से संतुलित रास्तों की ओर ले जाना, इस तरह कि श्रमिकों और समुदायों के लिए न्याय, गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह अवधारणा केवल जीवाश्म ईंधनों (fossil fuels) को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों और वास्तविकताओं को समेटती है, जैसे:

- ऊर्जा प्रणालियाँ (कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, तापीय बिजली)
- कृषि और कृषि-पारिस्थितिकी में बदलाव
- परिवहन और गतिशीलता की प्रणालियाँ
- औद्योगिक पुनर्गठन और शहरी परिवर्तन
- भूमि उपयोग, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और संसाधनों का शासन

भारतीय संदर्भ में, यह परिवर्तन कई स्तरों पर और एक-दूसरे से जुड़े रास्तों में घटित होता है। एक ओर, यह कार्बन-प्रधान क्षेत्रों से हटकर वैकल्पिक ऊर्जा और अवसंरचना—जैसे बड़े सौर पार्क, विशाल जलविद्युत परियोजनाएँ या परमाणु ऊर्जा—की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, जो स्वयं भी समानता, भूमि और आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं।

दूसरी ओर, कई क्षेत्रों में अभी भी कोयला, तापीय ऊर्जा और अन्य खनन-आधारित उद्योगों का विस्तार जारी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ, पारिस्थितिकी और सामाजिक संरचनाएँ बदल रही हैं।

इसलिए, न्यायपूर्ण परिवर्तन को इन दोनों प्रक्रियाओं—परिवर्तन और विस्तार—के साथ जुड़कर समझना होगा। इसमें न्याय, आजीविका, पारिस्थितिक सीमाएँ और समुदायों की भागीदारी जैसे प्रश्नों को केंद्र में रखना आवश्यक है। इसे बाद में जोड़े जाने वाले विचार के रूप में नहीं, बल्कि विकास के रास्तों में एक निरंतर और अभिन्न प्रक्रिया के रूप में शामिल करना होगा।

वैचारिक रूपरेखा: भारतीय संदर्भ में न्यायपूर्ण परिवर्तन की पुनर्कल्पना

न्यायपूर्ण परिवर्तन को केवल ऊर्जा प्रणालियों या तकनीकी बदलाव तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता। मूल रूप से यह समाज के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक ढाँचे में गहरे बदलाव की प्रक्रिया है।

ये परिवर्तन पूरी तरह नए नहीं हैं। ये दशकों से जारी हैं, अक्सर उन प्रमुख विकास मॉडल्स के साथ टकराव में, जिनका अनुसरण भारत और वैश्विक दक्षिण के कई देशों ने किया है। ये मॉडल मुख्यतः पूंजी-प्रधान,

ऊर्जा-प्रधान और केंद्रीकृत रहे हैं, जिनमें पुनरुत्थान (regeneration) के बजाय दोहन (extraction), टिकाऊपन के बजाय विस्तार, और समानता के बजाय केवल विकास (growth) को प्राथमिकता दी गई है।

इस प्रक्रिया में, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्थाओं, पारिस्थितिक संतुलन और सामुदायिक स्वायत्तता पर आधारित वैकल्पिक रास्तों को लगातार हाशिए पर रखा गया है। ये रास्ते, जो स्थानीय ज्ञान प्रणालियों और सामूहिक शासन पर आधारित हैं, मुख्यधारा के विकास विमर्श में कभी केंद्रीय स्थान नहीं पा सके।

जैसे-जैसे जलवायु संकट गहराता जा रहा है, इन वैकल्पिक कल्पनाओं को फिर से समझने और अपनाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है—चाहे वे ऐतिहासिक रूप से मौजूद रही हों या वर्तमान में उभर रही हों। यह अतीत में लौटने की बात नहीं है, बल्कि उससे सीख लेते हुए ऐसे नए भविष्य की कल्पना करने की है जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो।

साथ ही, न्यायपूर्ण परिवर्तन से जुड़ी चर्चाओं में एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती यह है कि इसे अक्सर वैश्विक नीतिगत ढाँचों—खासकर यूरो-अमेरिकी—के भीतर समाहित कर लिया जाता है, जहाँ इसे एक नए कार्यक्रम, वित्तीय साधन या तकनीकी बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संदर्भ में यह दृष्टिकोण सीमित साबित हो सकता है।

न्यायपूर्ण परिवर्तन के मौजूदा प्रवेश बिंदु

न्यायपूर्ण परिवर्तन के कई आधार पहले से ही विभिन्न नीतियों, व्यवस्थाओं और संघर्षों में मौजूद हैं। सवाल कुछ पूरी तरह नया बनाने का नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे नए नजरिए से समझने, पुनः अपनाने और नई दिशा देने का है।

उदाहरण के तौर पर:

- वन अधिकार अधिनियम**, 2006** प्राकृतिक संसाधनों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण का ढाँचा प्रदान करता है, विशेषकर आदिवासी और वन-आश्रित समुदायों के लिए। यह संरक्षण और आजीविका दोनों को मजबूत कर सकता है।
- रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)—जिसे हाल ही में विकसित भारत गारंटी रोज़गार एवं आजीविका मिशन *(ग्रामीण) अधिनियम, 2025* से प्रतिस्थापित किया गया है—को केवल मजदूरी तक सीमित न रखकर पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, भूमि सुधार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करने के साधन के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि हालिया बदलावों पर काफी आलोचना भी हुई है।
- श्रम कल्याण बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और स्किल इंडिया जैसी पहलें पहले से ही ऐसे संस्थागत और वित्तीय ढाँचे प्रदान करती हैं, जो परिवर्तन के रास्तों में उपयोगी हो सकते हैं।

मुख्य चुनौती इन व्यवस्थाओं को एक व्यापक, न्यायपूर्ण और पुनरुत्थानकारी परिवर्तन की दृष्टि से जोड़ने, पुनः उपयोग करने और एकीकृत करने की है।

इसके लिए कई स्तरों पर सोचने की आवश्यकता है:

- मौजूदा ढाँचों में बेहतर क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करना
- जहाँ वर्तमान व्यवस्थाएँ अपर्याप्त हैं, वहाँ नए दृष्टिकोण विकसित करना
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदायों की भूमिका को केंद्र में रखना

सामुदायिक भागीदारी और शासन

पूर्ववर्ती विकास मॉडलों—और कई वर्तमान परिवर्तन ढाँचों—की एक बड़ी सीमा यह रही है कि समुदायों को हाशिए पर रखा गया। जिन लोगों पर पर्यावरणीय क्षरण, संसाधनों के दोहन और आर्थिक बदलावों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, उन्हें इन प्रक्रियाओं को आकार देने में सबसे कम अवसर मिला है।

यदि परिवर्तन वास्तव में न्यायपूर्ण होना है, तो समुदायों को केंद्र में रखना होगा—सिर्फ लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाले, ज्ञान के स्रोत और संसाधनों के संरक्षक के रूप में।

परियोजना के बाद संसाधनों का रूपांतरण

जब खनन, औद्योगिक या अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ समाप्त होती हैं या संसाधन खत्म हो जाते हैं, तो वे पीछे केवल क्षतिग्रस्त परिदृश्य ही नहीं छोड़तीं, बल्कि नए प्रकार के संसाधन भी छोड़ जाती हैं—जैसे भूमि, जल स्रोत, वित्तीय प्रावधान और संस्थागत व्यवस्थाएँ।

मुख्य सवाल यह है कि इन बाद के संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए:

- क्या इन संसाधनों को समुदायों को वापस सौंपा जा सकता है?
- क्या इन्हें सामूहिक रूप से पुनर्जीवित और पुनः उपयोग में लाकर दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है?
- क्या परियोजना-समापन को परित्याग के बजाय पुनर्निर्माण के अवसर के रूप में देखा जा सकता है?

उदाहरण के लिए, बड़े बांधों से बने जलाशय मछली पालन जैसी नई आजीविका के अवसर पैदा करते हैं, जो यदि सामूहिक रूप से संचालित हों, तो प्रभावित समुदायों के लिए सहारा बन सकते हैं।

ये प्रश्न गहरे राजनीतिक हैं और भूमि, अधिकारों तथा शासन से जुड़े मुद्दों से सीधे संबंधित हैं।

परिवर्तन के वित्तीय आयाम

परिवर्तन के वित्तीय पक्ष को अक्सर एक बाधा के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में पर्याप्त संसाधन पहले से मौजूद हैं।

उदाहरण के लिए, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), विभिन्न उपकर (cess), शुल्क (levies) और खनन, ऊर्जा, अवसंरचना तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से जुड़े बजटीय प्रावधान—ये सभी बड़े वित्तीय प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चुनौती यह है कि ये संसाधन अक्सर बिखरे हुए, कम उपयोग में लाए गए या कहीं और मोड़ दिए जाते हैं। न्यायपूर्ण परिवर्तन के दृष्टिकोण से आवश्यक है कि:

- इन वित्तीय प्रवाहों का समुचित आकलन (mapping) किया जाए
- पारदर्शिता को मजबूत किया जाए
- इन्हें पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और आजीविका के पुनर्निर्माण की दिशा में लगाया जाए

चाहे जंगल हों, तटीय क्षेत्र, नदी तंत्र या खनन क्षेत्र—समस्या केवल संसाधनों की कमी की नहीं है, बल्कि यह है कि उपलब्ध संसाधनों का शासन कैसे हो रहा है और उनका लाभ किसे मिल रहा है।

फेलोशिप के लिए निहितार्थ

इसी व्यापक संदर्भ में **JUST** फेलोशिप की कल्पना की गई है।

यह फेलोशिप पत्रकारिता, अकादमिक या नीतिगत विश्लेषण की पारंपरिक सीमाओं में पूरी तरह नहीं आती, बल्कि इनके बीच एक ऐसा स्थान बनाती है जो वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जमीनी जुड़ाव से आकार लेता है और परिवर्तन की राजनीतिक तथा सामाजिक जटिलताओं को समझता है।

इसका उद्देश्य उन उभरते विचारों और प्रयोगों का दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण करना है, जो परिवर्तन की प्रक्रियाओं में समुदायों को फिर से केंद्र में लाने का प्रयास करते हैं—चाहे वे लंबे समय से मौजूद वैकल्पिक दृष्टिकोण हों या वर्तमान के नए प्रयोग।

मूल रूप से, यह फेलोशिप इन प्रश्नों की पड़ताल करती है:

- जमीनी स्तर पर अभी कौन-कौन से परिवर्तन हो रहे हैं
- समुदाय इन परिवर्तनों को कैसे अनुभव करते हैं और उनका अर्थ कैसे निकालते हैं
- कौन-से वैकल्पिक रास्ते कल्पित किए जा रहे हैं या व्यवहार में लाए जा रहे हैं
- प्रमुख (dominant) और वैकल्पिक रास्तों के बीच कौन-से टकराव मौजूद हैं
- कौन-सी बाधाएँ परिवर्तन को न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण बनने से रोकती हैं
- इन बाधाओं का व्यावहारिक समाधान कैसे किया जा सकता है

यह रूपरेखा इस बात को स्वीकार करती है कि न्यायपूर्ण परिवर्तन केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन है, जिसमें सत्ता, निर्णय-प्रक्रिया और संसाधनों के वितरण पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है।

फेलोशिप का दृष्टिकोण

यह फेलोशिप इस वैचारिक रूपरेखा को जमीनी, क्षेत्र-आधारित अध्ययन के माध्यम से लागू करती है।

इसका आधार यह समझ है कि परिवर्तन केवल संरचनात्मक बदलाव नहीं होता, बल्कि लोगों के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। कई संदर्भों में समुदाय इसे इस रूप में महसूस करते हैं:

- आजीविका और आर्थिक सुरक्षा का नुकसान
- विस्थापन या हाशिए पर धकेला जाना
- ऐतिहासिक असमानताओं का नए रूपों में पुनरुत्पादन

साथ ही, कुछ उभरते हुए रास्ते वैकल्पिक संभावनाएँ भी प्रस्तुत करते हैं:

- समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण और पुनर्स्थापन
- कृषि-पारिस्थितिकी आधारित प्रथाएँ
- स्थानीय और सुदृढ़ आजीविका प्रणालियाँ
- सार्वजनिक संसाधनों और योजनाओं का नवाचारपूर्ण उपयोग

फेलोशिप इन टकरावों और संभावनाओं को दर्ज करने का प्रयास करती है, जिसके लिए यह:

- विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों (sectors) में अध्ययन को केंद्रित करती है
- प्रभावित समुदायों के साथ सीधे संवाद करती है
- शासन व्यवस्थाओं, वित्तीय प्रवाहों और संस्थागत ढाँचों का विश्लेषण करती है
- प्रमुख विकास मॉडल और वैकल्पिक रास्तों—दोनों की पड़ताल करती है

इस फेलोशिप की विशिष्टता

- **समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण:** यह फेलोशिप सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को समुदायों के दृष्टिकोण से समझती है।
- **जमीनी और क्षेत्र-आधारित दस्तावेज़ीकरण:** यह केवल कागज़ी अध्ययन (desk research) तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभवों और कहानियों को महत्व देती है।
- **विस्तृत प्रयासों से जुड़ाव:** यह फेलोशिप संगठन के भीतर चल रहे अन्य प्रयासों—जैसे न्यायपूर्ण परिवर्तन पर जन-सुनवाई और संबंधित पहल—से भी जुड़ी हुई है।

आगे के भागों में फेलोशिप की संरचना और उसके संचालन की रूपरेखा विस्तार से प्रस्तुत की गई है।

कार्यक्रम की रूपरेखा

- सहभागियों की संख्या**:** 5 फेलो
- अवधि**:** 4 महीने — जुलाई से अक्टूबर (संभावित)
- पात्रता**:** भारतीय नागरिक, जो शोधकर्ता, पत्रकार, प्रैक्टिशनर या स्वतंत्र लेखक हों। आवेदकों के पास आजीविका, श्रम, पर्यावरण या संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 2–3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

क्षेत्र और फोकस

JUST फेलोशिप विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील परिदृश्यों के साथ काम करेगी, जिनमें शामिल हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं):

- खनन और संसाधन दोहन वाले क्षेत्र
- औद्योगिक और उभरते औद्योगिक क्षेत्र
- ऊर्जा परिवर्तन (energy transition) के कॉरिडोर
- वे क्षेत्र जहाँ कार्बन-प्रधान अवसंरचना का विस्तार हो रहा है
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और पुनर्स्थापन वाले क्षेत्र
- कृषि, परिवहन और अवसंरचना जैसे क्षेत्र

इसके अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जाएगा:

- खनन के बाद के भविष्य (post-extractive futures) और संसाधन शासन
- सार्वजनिक वित्त और संस्थागत तंत्र के उपयोग पर
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के प्रतिस्पर्धी मॉडल्स पर

यह दृष्टिकोण उन प्रक्रियाओं को भी समझने की कोशिश करता है, जो कार्बन-प्रधान प्रणालियों से बाहर जाने के साथ-साथ, उनमें प्रवेश करने से भी जुड़ी हैं।

आउटपुट

प्रत्येक फेलो को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- एक विस्तृत लेख **(6,000–8,000** शब्द**):**
  किसी विशिष्ट परिवर्तन संदर्भ का गहराई से विश्लेषण और दस्तावेज़ीकरण, जो जमीनी स्तर के ज्ञान को समृद्ध करेगा।
- एक संक्षिप्त लेख **(**ऑप-एड**) (800–1,200** शब्द**):**
  विस्तृत लेख का सरल, सार्वजनिक रूप से साझा करने योग्य संस्करण।

सभी विस्तृत लेखों को संगठन द्वारा संकलित कर फेलोशिप के अंत में एक सामूहिक प्रकाशन (रिपोर्ट/संकलन) के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
संक्षिप्त लेखों के प्रकाशन की जिम्मेदारी फेलो की होगी, जिन्हें वे बाहरी मंचों पर प्रकाशित कर सकते हैं।

प्रस्तुतियाँ अंग्रेज़ी या हिंदी में की जा सकती हैं। भविष्य में, अधिक समावेशिता के लिए बहुभाषी प्रकाशन और व्यापक प्रसार के विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

सहायता

- वजीफा **:** रु. 40,000 प्रति माह
- यात्रा सहायता **(**यदि आवश्यक हो**):** रु. 10,000 तक

- मेंटॉरशिप : आवश्यकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जो फेलो की जरूरतों और मेंटर्स की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसमें संपादकीय सुझाव, समय-समय पर बातचीत (check-ins) और विषयगत मार्गदर्शन शामिल हो सकते हैं।
- भुगतान : फेलोशिप का वजीफा निर्धारित कार्यों और डिलीवेरेबल्स के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर जारी किया जाएगा।

अपेक्षित परिणाम

निकट अवधि के परिणाम

- जमीनी स्तर पर आधारित, संदर्भ-समृद्ध ज्ञान सामग्री का निर्माण
- पारिस्थितिक और आर्थिक परिवर्तन पर गहन और संतुलित दृष्टिकोणों तक व्यापक सार्वजनिक पहुँच
- विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े फेलो का समूह, जो स्थानीय संदर्भों पर आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करेगा
- शासन से जुड़ी चुनौतियों, वित्तीय अंतराल और उभरती हुई प्रथाओं का दस्तावेज़ीकरण

दीर्घकालिक परिणाम

- क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण परिवर्तन पर विमर्श को मजबूत करना
- समुदाय-नेतृत्व वाले रास्तों और समाधानों को अधिक दृश्यता मिलना
- भूमि पुनर्स्थापन, संसाधन शासन और आर्थिक विविधीकरण की प्रक्रियाओं में बेहतर जवाबदेही
- शोधकर्ताओं, प्रैक्टिशनरों और कथाकारों का एक मजबूत नेटवर्क, जो नीति और बहस को प्रभावित करे

निष्कर्ष

एक दृष्टि से देखें तो न्यायपूर्ण परिवर्तन का विचार नया नहीं है; यह उन लंबे संघर्षों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों से जुड़ा है, जिन्होंने प्रमुख विकास मॉडल्स को चुनौती दी है।

लेकिन दूसरी ओर, यह नया भी है, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ इन विचारों को फिर से व्यक्त करने, विस्तार देने और आपस में जोड़ने की मांग करती हैं।

आज हम विभिन्न रास्तों के बीच एक संगम—और कई बार टकराव—देख रहे हैं:
दोहन-आधारित बनाम पुनरुत्थान-आधारित, केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत, बहिष्करणकारी बनाम लोकतांत्रिक।

JUST फेलोशिप इस दौर को समझने और उससे जुड़ने का एक प्रयास है—ऐसे रास्तों को दर्ज करने, सवाल उठाने और आगे बढ़ाने का, जो हमें एक अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और पारिस्थितिक रूप से संतुलित भविष्य की ओर ले जाएँ।

Samata Assertion for people CFA Centre for Financial Accountability